SHRI SHANKAR ROY CHOWDHURY : Sir, I would like to know whether the Indian and the Bangladesh Governments have now worked out an accepted procedure by which the Bangladesh Government will accept illegal migrants being pushed back or deported to Bangladesh under the recent Foreign Secretary level talks ?

SHRI VINOD KHANNA : Sir, unfortunately, even up to this date, Bangladesh has not accepted that there is illegal migration in India. They don't even accept the fact that there is illegal migration in India. But, whenever we have investigated, verified these people, and taken them to the border, they have accepted these people; they have been cooperative with us. But there is no such established procedure by which they will take back the nationals whom we identify. After all we are the complainants. We have to prove that they are non-nationals; we have to prove that they are Bangladeshi nationals. Then, they will verify and take the people back.

श्री सभापति : मैं माननीय विदेश मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि यह समस्या सारे राज्यों में है। इस समस्या के संबंध में आप राज्यों की सरकारों के साथ बैठकर बात करें और कोई ऐसा प्रोसीजर निकालें जिस से आप को समय-समय पर जानकारी मिलती रहे और आप उन की रोकथाम कर सकें।

Mobile telephone facility

*662. SHRI KALRAJ MISHRA : Will the Minister of COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY be pleased to state:

(a) whether certain regions in the country are still deprived of the mobile telephone facility;

(b) if so, the details thereof and the reasons therefor; and

(c) the steps being taken to provide these areas with such facilities?

THE MINISTER OF COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY AND MINISTER OF DISINVESTMENT (SHRI ARUN SHOURIE): (a) to (c) A Statement is laid on the Table of the House.

(a) Yes, Sir.

(b) and (c) Consequent to the grant of licenses for Cellular Mobile Telephone Service (CMTS) to private operators, Cellular Services were first started in the four Metro City Service Areas of Delhi, Mumbai, Kolkata and Chennai from August, 1995 onwards and thereafter in the Telecom Circle Service Areas beginning December, 1996. After adoption of New Telecom Policy-1999

(NTP-99) and shifting of the existing operators to the revenue sharing regime of NTP-99, additional licenses were granted to private operators. The cellular service has been progressively rolled out by the private operators in the district headquarters and towns. According to information furnished by the Cellular Operators Association of India, about 1640 district headquarters and towns in various service areas across the country had been covered with the cellular service by March, 2003. Mahanagar Telephone Nigam Ltd. started its cellular services from February, 2001 in Delhi and Mumbai. Bharat Sanchar Nigam Limited (BSNL) also started providing the services in most parts of the country from October, 2002 and have so far covered about 1020 cities and towns with the cellular service by March, 2003. Private operators coupled with the Government operators are expected to cover more and more places with the Cellular Service over a period of time.

The terms and conditions of the Licence for CMTS require that in the Metro City Service Areas an operator has to cover 90% of the Service Area within one year, and in the Telecom Circle Service Areas, 10% of the District Headquarters within one year and 50% of the District Headquarters within three years. The licensee is also permitted to cover any other town in a district in lieu of the District Headquarter. The choice of District Headquarters/towns to be covered and further expansion beyond 50% District Headquarters/towns shall lie with the licensee depending on his business decision. There is no mandatory requirement for coverage of 100% of the districts as well as coverage of rural areas.

Expansion or fresh start of CMTS in J&K, Assam and North East Telecom Circles was not permitted earlier on considerations of security. This was however permitted with effect from 21st August, 2002. Accordingly, BSNL has plans to launch its cellular services in Jammu and Kashmir in the near future. BSNL also has plans to launch its cellular services in Assam and North East Telecom Circles during the current financial year.

श्री कलराज मिश्र : सभापति जी, मंत्री जी ने अपने उत्तर में दिया है कि निजी प्रचालकों के द्वारा, जो निजी मोबाइल सेल्युलर कंपनी हैं उनके द्वारा जिला मुख्यालयों और मुख्य-मुख्य शहरों में ही ज्यादातर यह सुविधा प्रदान की गई हैं, भारत के अधिकांश ग्रामीण क्षेत्र इससे वंचित हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि कितने प्रतिशत क्षेत्र हैं, जो इस सुविधा से वंचित हैं और इसके साथ ही साथ इस दसवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत जो ऐसे सुविधारहित क्षेत्र हैं उनमें कितने स्थानों पर यह सुविधा प्रदान की जाएगी ?

श्री अरुण शौरी : सभापति जी, एक्चुअली यह सेल्युलर मोबाइल टेलीफोन की ग्रोथ इंडिया में बहुत फास्ट हुई है, आज लगभग 1.2 करोड़ सब्सक्राइबर इसके हैं। इसमें सबसे ज्यादा तेजी से पिछले 7-8 महीने में जो सर्विस एक्सटेंड कर रहे हैं, वह एक्चुअली प्राइवेट कंपनी नहीं हैं बल्कि बीएसएनएल है। इसने पिछले 7-8 महीने में 22.5 लाख सब्सक्राइबर कैप्चर किए हैं। मिश्रा जी की यह बात ठीक है कि पहले ऐसी समस्या मेट्रोपोलिटन शहरों में आएंगी। आपको सुनकर खुशी होगी कि आज 1640 डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर और छोटे टाऊन, कस्बों में यह सर्विस फैल चुकी है। जैसे-जैसे यह टॉवर एक्सटेंड होते जाएंगे तो नेचुरली विलेज एरिया भी कवर होंगे। दसवीं योजना में तो इसका एक्सटैंशन होने की बहुत ही जरूरत है और जैसा मैंने पिछली बार आपसे अर्ज किया था, बीएसएनएल को इसमें तकरीबन 29 हजार करोड़ रुपया चाहिए और अगर हम उसको फैसिलिटी नहीं देंगे या रिसोर्स कमाने नहीं देंगे तो दिक्कत होगी। इसमें कोई शंका नहीं कि इस प्लान में इन्हें केवल 4 करोड़ रुपए ही दिए गए हैं अगले चार साल के लिए।

श्री कलराज मिश्र : मान्यवर, निजी मोबाइल सेल्युलर कंपनी हैं उनकी सेवाएं हैं उसकी दर में लगातार कमी हो रही है, वे अपने रेट घटाते चले जा रहे हैं, लेकिन सरकार स्तर पर बेसिक फोन सेवा की जो दरें हैं, वे बढ़ाने के हिसाब से बनाई जा रही हैं। यह एक अति गंभीर विषय दिखाई पड़ता है। तो क्या माननीय मंत्री जी इस संबंध में विचार करते हुए उस सेवा की दरों को घटाने की दिशा में प्रयत्न करेंगे, जिसके कारण किसी प्रकार की आशंका आम आदमी के मन में न निर्माण हो ?

श्री अरुण शौरी : सर, एक्चुअली हरेक तरह से टेलीफोन रेट बहुत कम हो रहे हैं, ... **(व्यवधान)** ...

श्री सभापति : सुनिए, सुनिए। आप सुनिए। ... **(व्यवधान)**

SHRI ARUN SHOURIE : Sir, I will come to that....*(Interruptions)*

SHRI A. VIJAYARAGHAVAN : Sir, the Minister is not paying from his own pocket. ....*(Interruptions)*

श्री सभापति : यह मैं एलाऊ नहीं करूंगा। आप सुनिए मंत्री जी क्या कह रहे हैं ? ... **(व्यवधान)** ...

SHRI ARUN SHOURIE : Sir, there is one element which is of great concern to the Members and to the general public. I entirely agree. But in the new order of TRAI, charges for calls from fixed lines to cellular lines, उनमें क्योंकि पल्स रेट 60 सेकेंड कर दिए गए हैं और उसके चार्ज जरूर ज्यादा हो गए हैं। ...*(Interruptions)*

श्री सभापति : आप सुनिए तो सही। ... **(व्यवधान)** ...

SHRI ARUN SHOURIE : Sir, all the other rates are coming down. आप इजाजत दें तो मैं बता दूं।

श्री सभापति : जी, बता दीजिए। ... **(व्यवधान)** ...

श्री अरुण शौरी : सर, मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि जो आपकी बहुत स्ट्रोंग फीलिंग है, वह मैं ट्राइ के चेयरमैन को और मैम्बर को आज ही बतलाऊंगा। कल भी मैंने उनसे बात की है, आज भी बतलाऊंगा, मगर इसमें कोई सात-आठ महीने की कंसलटेशन के बाद उन्होंने यह सब रेट तय किए हैं। एक रेट को तय किया जाएगा तो फिर यह होगा कि रूरल एरिया के लिए जो रिसोर्स चाहिए वह नहीं हो पाएंगी, मगर आपकी आशंका मैं जरूर सबको पहुंचाऊंगा। ... **(व्यवधान)** ... मगर जो न चेंज हो, आप मुझे बताएंगे कि क्या-क्या नहीं चेंज चाहिए क्योंकि इसमें बहुत भ्रम है। बीएसएनएल के रेट में जो मंथली रेंट है, न तो रूरल सब्सक्राइबर के लिए और ही अर्बन सब्सक्राइबर के लिए चेंज किया गया है। लोकल कालस के लिए पल्स रेट जो 180 सैकिंड्स का था, जिसको ''टीआरएआई'' ने कहा था कि कम करो, वह कम नहीं किया गया। आईएसडी कालस के लिए काल रेट्स चेंज नहीं किया गया। रूरल सब्सक्राइबर की जो डेफिनेशन ''टीआरएआई'' ने चेंज की थी, जैसा मैंने आपसे पहले अर्ज किया था, हमने उनको रिप्रजेंट किया—क्योंकि अगर हम उस डेफिनेशन को चेंज करते तो रूरल सब्सक्राइबर जो करीब एक करोड़ हैं, उसमें से 80 लाख सब्सक्राइबर नान रूरल हो जाते—उन्होंने अपना वह आर्डर रिसिंड करके पुरानी डेफिनेशन रहने दी।

सर, एसटीडी कालस में बहुत कमी हुई है। आप देखिए कि एसटीडी काल जो विद इन दि सर्कल है, उसमें ''टीआरएआई'' ने 8.40 रुपए प्रति मिनट अलाऊ किया था, मगर ''बीएसएनएल'' ने उसको 2.40 रुपए प्रति मिनट रखा है, ''टीआरएआई'' ने भी कुछ सोचकर, कॉस्ट वगैरह का सोचकर और कितने रिसोर्सिज चाहिए, यह सोचकर वह किया था, यानी जैसे मध्य प्रदेश में आप कहीं से कहीं काल कर लीजिए, इतने बड़े प्रान्त में रेट अनचेंज रहेंगे। दूसरे जो इंटर सर्कल एसटीडी रेट्स हैं, वे वही रहेंगे, वे चेंज नहीं किए गए। फिक्स टू इंटर सर्कल एसटीडी कालस 200 किलोमीटर से ज्यादा, जो पहले 4.80 रुपए थी, उसे कम करके 3.60 रुपए प्रति मिनट रखा गया है जबकि ''टीआरएआई'' ने कहा था कि इनको इन्क्रीज़ कर दीजिए 8.40 रुपए प्रति मिनट। तो, सर, इसी तरह से बाकी चीजें हैं। यह एक प्वाइंट जरूर ठीक है, कई माननीय सदस्यों ने मुझे अभी कहा है और कल भी यह कहा गया है कि जो फिक्स लाइन से सेलुलर रेट्स हैं, वे क्योंकि ज्यादा कर दिए गए हैं, इसका लोगों पर बहुत बड़ा असर पड़ा है और उसमें यह भी इल्जाम लगाया जा रहा है कि गवर्नमेंट की कम्पनीज रेट इन्क्रीज़ कर रही हैं, इससे सेलुलर कम्पनीज को फायदा होगा। मैं इस बारे में उनसे जरूर बात करूंगा। सर, फाइनल अथॉरिटी उनकी

है। अंडर दि एक्ट, जो एक्ट आपने पास किया है, उसके अनुसार फाइनल अथॉरिटी उनकी है, मगर मैं उनसे बात करूंगा। *(Interruptions)* It is a policy decision. I will put it to the Prime Minister, *(Interruptions)*

श्री नीलोत्पल बसु : आप अमेंडमेंट क्यों नहीं लाते ? ....**(व्यवधान)** ....

SHRI N. K. PREMACHANDRAN : The hon. Minister should assure the House in this regard. *(Interruptions)*

श्री सभापति : श्री संजय निरुपम। ....**(व्यवधान)** ....

SHRI NILOTPAL BASU : This is the precise question we are raising. You have to define 'public interest', and amend the law. *(Interruptions)*

श्री सभापति : उन्हें बोलने दीजिए। श्री संजय निरुपम।

श्री प्रेम गुप्ता : सर, जब ''टीआरएआई'' को पास किया था तब सरकार ने यह कहा था कि हम पूरा कंट्रोल रखेंगे और अब बोलते हैं कि कोई कंट्रोल नहीं है।

श्री संजय निरुपम : सभापति जी, पिछले महीने भी जब इस विषय पर हमने आधे घंटे की चर्चा की थी तब भी मंत्री जी ने यही कहा था कि मैं ''टीआरएआई'' से बात करूंगा और कोशिश करूंगा कि सब लोगों को रिलीफ मिले। पता नहीं इन्होंने क्या बातचीत की। अंतत: जो बेसिक टेलीफोन यूजर हैं, जो इस देश में एक बहुत बड़ा वर्ग है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाला वर्ग है, उसके ऊपर इससे असर पड़ा है। मंत्री जी ने कहा कि सिर्फ पल्स रेट कम किया गया है। तीन मिनट का यदि एक मिनट करेंगे तो वैसे ही टैरिफ बढ़ जाएगा। तो पहला तो मेरा निवेदन यह है कि अगर ''टीआरएआई'' का बिल हमने पास किया और उस कानून के तहत आप उनके मामले में इंटरफियर नहीं कर सकते तो ''टीआरएआई'' के बारे में एक अमेंडमेंट लाया जा सकता है।

सभापति जी, दूसरे ''टीआरएआई'' में एक प्रोविजन है कि पब्लिक इंटरेस्ट में सरकार कभी भी ''टीआरएआई'' के किसी भी डिसीजन को रोक सकती है। तो पब्लिक इंटरेस्ट यह है कि बेसिक टेलिफोन मंहगा हो चुका है। अब बेसिक टेलिफोन महंगा हो चुका है तो उसको सस्ता करने के लिए, हम सबकी मांग के अनुसार, जितनी जल्दी हो सके क्या माननीय मंत्री जी इस पूरे नए टैरिफ को रोल बैक करेंगे ?

श्री सभापति : मंत्री जी, एक बात मैं भी जानना चाहता हूं क्योंकि मैं उस समय यहां नहीं था जिस समय यह ''टीआरएआई'' का कानून पास हुआ था कि क्या इस कानून में यह व्यवस्था है कि सैंट्रल गवर्नमेंट यदि चाहे तो वह ''टीआरएआई'' को निर्देश दे सकती है ?

श्री नीलोत्पल बसु : हां, दे सकती हैं ....**(व्यवधान)**....

श्री सभापति : एक मिनट ठहर जाइए। ....(**व्यवधान**)..... सबको बोलने की जरूरत नहीं है।

श्री संजय निरुपम : सर, एक प्राविजन है। मंत्री जी को सब मालूम है। ''टीआरएआई'' की एक धारा यह कहती है कि अगर ''टीआरएआई'' का कोई निर्णय जनहित के खिलाफ है तो सरकार उस निर्णय के मामले में इंटरफियर करके ''टीआरएआई'' के निर्णय को रोक सकती है। यह व्यवस्था है।

श्री अरुण शौरी : सर, ''टीआरएआई'' का जो एक्ट है, उसमें ....(**व्यवधान**)....

श्री सभापति : मंत्री जी, आप बोलिए।

श्री अरुण शौरी : मेरे लिए बहुत आसान है यह कह देना कि रोल बैक कर दूंगा या यह कर दूंगा, मगर ऐसा कहना बिल्कुल ठीक नहीं होगा। वह सैक्शन मैंने पिछली बार भी पढ़ा था, जब नीलोत्पल जी ने यह क्वेश्चन उठाया था। उसमें आप देखिए कि किस चीज के कारण आपने अथॉरिटी दी है। Power of the Central Government to issue directions आपने यही सवाल पूछा था? The Central Government may, from time to time, issue to the authority such directions as it may think necessary in the interest of :

sovereignty and integrity of India;
security of the State;
friendly relations with foreign States;
public order, decency or morality. *(Interruptions)*

श्री सभापति : आप बैठ जाइए। ....(**व्यवधान**)..... आप यह कर क्या रहे हैं? संजय निरूपम, कृपया आप यह बता दीजिए कि डायरेक्शन यही हैं न जो आपने सुने हैं?

श्री संजय निरुपम : मेरे ख्याल से आर्टिकल 53 है।

श्री अरुण शौरी : सैक्शन 25 है।

SHRI SANJAY NIRUPAM : Yes.

श्री सभापति : अब यह कानून आपने पास किया, डायरेक्शन क्या दिए जा सकते हैं, इस संबंध में आपने व्यवस्था की है। अब इस संबंध में जो डायरेक्शन दिए गए हैं, जो आपके रेट्स बढ़े हैं वे इस संबंध में तो हैं नहीं, अब गवर्नमेंट क्या करेगी, यह बता दीजिए।

श्री संजय निरुपम : सभापति जी ....(**व्यवधान**)....

SHRI JANARDHANA POOJARY : The Government can give direction. ...*(Interrruptions)*... The Government can give direction if it feels that there is something against the country. ...(Interruptions)...

श्री सभापति : ठहरिए आप ...**(व्यवधान)**...

SHRI JANARDHANA POOJARY : You repeal the Act...*(Interruptions)*...

श्री सभापति : नहीं, रिपील नहीं कर सकते, वह कानून आपने पास किया है ...**(व्यवधान)**... I will not allow ...*(Interruptions)*.... Nothing will go on record. बिल्कुल नहीं ...*(Interruptions)*...

SHRI JANARDHANA POOJARY :*

SHRI N. K. PREMACHANDRAN :*

SHRI NILOTPAL BASU :*

SHRI MANOJ BHATTACHARYA :*

SHRI JANARDHANA POOJARY : The country is supreme. ...*(Interruptions)*... The Parliament is supreme .....*(Interruptions)* ... They can come forward with an amendment .....*(Interruptions)*....

श्री सभापति : मैं मानता हूं कि पार्लियामेंट सुप्रीम है ...**(व्यवधान)**... आप बैठिए। क्वेश्चन यह नहीं है ...**(व्यवधान)** यह कानून किसने पास किया है ? आप यह कहिए कि गर्वनमेंट इसमें अमेंडमेंट करे तो बात समझ में आती है। अब गुस्सा करने से कोई फायदा नहीं है ...**(व्यवधान)**

श्री संजय निरुपम : सभापति जी, मेरा निवेदन यह है कि टेलीकॉम सैक्टर में रोज विस्तार हो रहा है, विकास हो रहा है। आपने पूछा कि TRAI किसने पास किया ? बिल्कुल हमने पास किया है लेकिन ... **(व्यवधान)** ...

श्री सभापति : आप बैठिए तो सही ...**(व्यवधान)** ...

श्री संजय निरुपम : अगर किसी क्लाज से जनता के हित के खिलाफ कुछ काम हो रहा है तो सरकार की यह जिम्मेदारी बनती है कि वह उसमें अमेंडमेंट लाए और जनता के हित के बारे में पहले सोचे ... **(व्यवधान)** ...

श्री सभापति : मैं एलाऊ नहीं करूंगा, Nothing will go on record. ...*(Interruptions)*... आपका क्वेश्चन यह था कि क्या गर्वनमेंट TRAI के प्रपोजल के मामले में उनको खत्म करने या चेंज करने की डायरेक्शन दे सकती है ? नहीं, as per Act वह डायरेक्शन नहीं दे सकती ...

*Not recorded.

(व्यवधान) ··· पब्लिक आर्डर नहीं आएगा। आप ज्यादा से ज्यादा मंत्री महोदय को हाऊस की तरफ से यह कहिए कि इसके ऊपर वे विचार करे, TRAI से बात करे और यदि कानूनी अधिकार देना है तो माननीय सदस्य उस एक्ट में अमेंडमेंट मूव कर दें, उस पर विचार हो जाएगा। अब यह मामला आगे नहीं चलेगा। Next Question.

श्री लालू प्रसाद : सभापति महोदय, आपने हमको आश्वस्त किया था कि आप हमको सवाल पूछने देंगे लेकिन फिर आप आगे बढ़ गए।

श्री सभापति : आप भले आदमी हो, आप क्या टेलीफोन की बात करते हो।

श्री लालू प्रसाद : नहीं, हम तो दूसरी बात कहना चाहते हैं।

श्री सभापति : आप विश्वास करिए, जो मैंने कहा है ··· **(व्यवधान)** ···

डा. अबरार अहमद : महोदय, इधर से किसी को मौका नहीं दिया गया ··· **(व्यवधान)**

श्री सभापति : मौका सबको दिया जा रहा है, ऐसी बात नहीं है। यह गलत बात मत कहिए ··· **(व्यवधान)** आप बैठिए।

श्री लालू प्रसाद : सभापति महोदय, यह फोन एक भारी झंझट का घर है। इससे अपराधियों का चारों तरफ संपर्क कायम होता है। आप इसको बंद करिए, समाप्त करिए। पहले जो P&T का था, उसी को रखिए। इसके द्वारा सारे अपराधी मलेशिया से, थाईलैंड से मॉनीटरिंग कर रहे हैं ···**(व्यवधान)** ··· घर से फोन आता है कि कहां पर हो ? पति को बोलना पड़ता है कि हम चांदनी चौक पर पहुंच गए हैं। हटाइए इसको।

श्री सभापति : जिन पत्नियों को पतियों पर विश्वास नहीं होता, वे ऐसा काम करती हैं। अगर आप में विश्वास नहीं है तो यह हाऊस की जिम्मेदारी नहीं है ··· **(व्यवधान)**

BSNL's commercial operation in A.P.

*663. SHRI S. M. LALJAN BASHA : Will the Minister of COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY be pleased to state :

(a) whether it is a fact that BSNL has not rationalised its commercial operation in Andhra Pradesh;

(b) what is the new system for payment of bills which are delayed by a few days;

(c) whether it is a fact that customers have to travel 70 miles or more to pay bills which are delayed;